डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 फरवरी, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 फरवरी, 2025

| वर्ष 68 | अंक 17 | भोपाल | 1 फरवरी, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में नागरिक दें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान : राज्यपाल श्री पटेल

संविधान से मिले अधिकारों कर्तव्यों का निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करें पालन

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराया

भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

भोपाल :राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर नागरिकों से आह्वान किया है कि वें एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। संविधान से मिले अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों का अपने आचरण और व्यवहार में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पालन करें। स्वतंत्रता सेनानियों, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि प्रदेश में गण और तंत्र, समान भाव, समर्पण और लगन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्म-निर्भर भारत की परिकल्पना को मूलमंत्र बनाकर जनसेवा, सुशासन और प्रदेश के चहुमुखी विकास की नई यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आकाश में गुब्बारे छोड़े और परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परम्परागत लोकनृत्यों और झांकियों की प्रस्तुति का अवलोकन किया। परेड कमांडरों के साथ ग्रुप फोटो भी खिचवाया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के पर्यावरण के लिए नव जागृति की पहल "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान में प्रदेश ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाकर, जल गंगा संवर्धन अभियान में बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर सजग-सक्रिय गणतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश युवाओं, महिलाओं, अन्नदाता किसानों और गरीब वर्ग की समान रूप से उन्नति उनके जीवन को खुशहाल, आसान बनाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी अधोसंरचना और औद्योगिक क्षेत्र में विकसित प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सशक्तिकरण पर आधारित चार मुख्य स्तंभों पर कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में मिशन मोड में कार्य करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन, स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन, किसान-कल्याण और देवी अहिल्याबाई होल्कर नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किये हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए निवेश और औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मध्यप्रदेश, देश और दुनिया के उद्योग समूहों के लिए निवेश का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बल देते हुए संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किये गये हैं। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम और शहडोल के कॉन्क्लेव और माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित की गई। प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए सरकार ने यू.के. एवं जर्मनी में रोड शो कर खनिज, सेमी कंडक्टर, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्र-संस्करण जैसे क्षेत्रों में 78 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। फरवरी-2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की निवेश संभावनाओं को विस्तारित करने के लिए मुम्बई, कोयम्बटूर, बैंगलुरू, कोलकाता और पुणे में रोड शो किये गये हैं। इन सभी प्रयासों से अब तक लगभग 4 लाख 17 हजार करोड़ का निवेश और 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की अमृत पीढ़ी के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के आवश्यक संसाधन, अवसर प्रदान करने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। युवा आत्म-निर्भर बन कर सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाए, इसके लिए उनकी शिक्षा, कौशल उन्नयन एवं स्व-रोज़गार की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन के सफल परिणाम मिलने लगे हैं। हमारा प्रदेश कृषि क्षेत्र में हमेशा देश में अग्रणी रहा है। किसान भाइयों को उनकी मेहनत की सही कीमत दिलाने से लेकर शून्य ब्याज दर पर ऋण, सिंचाई सुविधाओं के निरंतर विस्तार तथा उनकी हर ज़रूरत और मुश्किल घड़ी में सहायता सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आजीविका के साथ सेवा की नवीन संकल्पना के साथ गौ-संरक्षण और संवर्धन के लिये अनेक नई और अभूतपूर्व पहल की है। गरीबों के कल्याण का हमारा संकल्प अब सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के गरीब वर्ग को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए बराबर के अवसर और सुविधाएँ सुनिश्चित होने से वह सम्मान और आत्म-विश्वास के भाव से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख और शहरी में 44 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है। पीएम स्वामित्व योजना में 24 लाख से अधिक भू-अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष-2047 तक सिकलसेल रोग उन्मूलन के संकल्प की पूर्ति की दिशा में प्रदेश में सक्रियता से काम हो रहा है। मध्यप्रदेश में सिकलसेल स्क्रीनिंग के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक स्क्रीनिंग कर, देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। अब तक वर्ष 2025 की स्थिति में करीब 90 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच कर शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है। अनुसूचित जनजाति बहुल विकास खण्डों में 53 लाख 87 हजार से अधिक आबादी को जेनेटिक कॉउसिंलिंग कार्ड वितरित कर देश में प्रथम स्थान पर है। सरकार द्वारा सिकलसेल प्रभावितों का नि:शुल्क उपचार प्रबंधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय की तरक्की के हर पहलू का ख्याल रख रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए किया गया है, जिसका लाभ लगभग 35 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन हेतु 24x7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय 4 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 8 हजार किया जायेगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

संविधान कराता है गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में फहराया राष्ट्र-ध्वज

उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व-गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और सभी सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुँमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन-सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्यप्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के लगभग साढ़े आठ करोड़ नागरिकों को जाता है, जो इस पहचान के शिल्पकार रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुरूप विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है।

संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्सव, उमंग और देशभक्ति के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जोश और जुनून के साथ उत्साह भरे वातावरण में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झण्डावंदन किया। उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा आकर्षक एवं नयनाभिराम झांकियां भी निकाली। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी शॉल-श्रीफल देकर सम्मानित किया।

केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर देश भर से आमंत्रित 200PACS प्रतिनिधियों से नई दिल्ली में संवाद किया

गणतंत्र दिवस परेड में PACS प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रित करना ग्रामीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और साथ ही यह PACS को न केवल वित्तीय गतिविधियों बल्कि सामुदायिक कल्याण का केंद्र भी बनाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को बहु-उद्देशीय संस्थानों के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है

PACS का डिजिटलीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम, इससे वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा मिला है

नई दिल्ली,केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर देशके 13 राज्यों से आए 100 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों से नई दिल्ली में संवाद किया।इस अवसर पर सहकारिता सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस परेड में PACS प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रित करना ग्रामीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और साथ ही यह PACS को न केवल वित्तीय गतिविधियों बल्कि सामुदायिक कल्याण का केंद्र भी बनाएगा।

कार्यक्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मूर कश्मी,र से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। इन राज्यों के PACS कंप्यूटरीकरण का काम प्रभावी ढंग से जारी है और उनके संबंधित पैक्सल कर्मी डिजिटलीकरण का लाभ उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को बहु-उद्देशीय संस्थानों के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है।भारत सरकार अन्यइ हितधारकों जैसे नाबार्ड, राज्यस सरकार और सहकारी बैंकों के साथ मिलकर PACS को सहकार से समृद्धि की परिकल्पदना को यथार्थ में साकार करने के लिए सशक्त् कर रहा है। यह पहल 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूसटरीकरण' की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का हिस्सा है जिसका लक्ष्यक देश भर में पैक्सह की पारदर्शिता, कार्यकुशलता और लाभप्रदता में वृद्धि करना है। इस परियोजना द्वारा 67,930 PACS के कंप्यू टरीकरण का लक्ष्य है जिससेतीव्र ऋण संवितरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उन्त बैंकिंग सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार के साथ-साथ अन्न् भंडारण, कॉमन सेवा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों जैसे गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी । PACS का डिजिटलीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम, इससे वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा मिला है।

PACS के सुदृढ़ होने से ग्रामीण समुदाय सशक्त् होंगे और समावेशी विकास की भारतीय परिकल्पमना साकार होगी । गणतंत्र दिवस परेड के लिए PACS प्रतिनिधियों को दिया गया निमंत्रण ग्रामीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

'खेत से उपभोक्ता' मॉडल से किसानों को मिलेगा सही मूल्य, बिचौलियों का होगा अंत

दिल्ली | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर किसानों से मुलाकात की और MSP जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सही मूल्य दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने "खेत से उपभोक्ता" मॉडल को किसानों के मुनाफे के लिए महत्वपूर्ण बताया. चौहान ने टिकाऊ खेती और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार के प्रयासों पर भी जोर दिया.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के पूसा परिसर में किसानों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने किसानों की भूमिका, कृषि सुधार और सरकार की नीतियों पर चर्चा की. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "किसान हमारे भगवान हैं और उनकी सेवा करना भगवान की सेवा के समान है." मंत्री ने किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी पहलों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

किसानों के लिए सरकार की योजनाएं

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतमसमर्थनमूल्य (MSP) जैसी योजनाओं पर काम कर रही है. उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया. इसके अलावा, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया.

बिचौलियों को खत्म करने की योजना

चौहान ने सरकार के "खेत से उपभोक्ता" मॉडल पर प्रकाश डाला. इस मॉडल का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाना है. इससे किसानों को उनकी मेहनत का अधिक मुनाफा मिल सकेगा. उन्होंने कहा, "यह मॉडल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उन्हें बेहतर आर्थिक स्थिति में लाएगा."

टिकाऊ कृषि पद्धतियां और जागरूकता

मंत्री ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और इससे जुड़ी पहलों की जानकारी दी. इनका उद्देश्य न केवल उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि किसानों की लाभप्रदता को भी सुनिश्चित करना है. उन्होंने प्राकृतिक खेती और पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों की चर्चा करते हुए कहा कि इनसे खेती को टिकाऊ और भविष्य के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है.

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया

श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन भी किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता आने वाले दिनों में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारी संस्थाओं की समृद्धि, सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और हर व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे

मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सहकारिता क्षेत्र, सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है

देशभर में Cooperation Amongst Cooperatives के सिद्धांत पर चल सहकारिता क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा

जल्द ही सभी सहकारी बैंक सामान्य बैंकों की सेवाओं से युक्त होंगे, जिससे सहकारी बैंकिंग का विकास होगा

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजित पवार और सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष मनाने के लिए 12 माह का एक कार्यक्रम तय किया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सहकारिता वर्ष इस तरह से मनाया जायेगा जिससे देशभर में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता के विस्तार, इस क्षेत्र में शुचिता लाने, सहकारी संस्थाओं को समृद्ध बनाने, कई नए क्षेत्रों में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और भारत के हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 को जब सहकारिता वर्ष समाप्त होगा, तब तक हमारी सहकारिता का विकास सिमेट्रिक और समावेशी होगा और हम सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर चुके होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। सहकारिता क्षेत्र, सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां सहकारी बैंकों के अंब्रेला संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। यह संगठन अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को मल्टीडायमेंशनल फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक अगले 3 साल में राष्ट्रीय बैंकों और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से युक्त हो जाएंगे जिनसे हमारी सेवाओं का विस्तार होगा। इसके साथ-साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और सभी कोऑपरेटिव बैंकों के अकाउंटिंग सिस्टम को एक करना इसका लक्ष्य रहेगा। श्री शाह ने कहा कि भारत में कुल 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में हैं, देश में 49 शेड्यूल्ड बैंक हैं और 8 लाख 25 हज़ार से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में Cooperation Amongst Cooperatives को लागू किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन और विदेश के साथ व्यापार जैसी गतिविधियों को अर्बन कोआपरेटिव बैंक के साथ समाहित करने का काम 'अंब्रेला संगठन' करेगा। कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेनदेन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगा। श्री शाह ने कहा कि Cooperation Amongst Cooperatives के सिद्धांत को देश के सभी राज्यों में ज़मीन पर उतरने से हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी और तभी सहकारिता क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के कई सारे मुद्दे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सुलझाए हैं। आने वाले दिनों में अंब्रेला संगठन को मज़बूत कर हम विश्वास और व्यापार को बढ़ाएंगे और सभी अड़चनों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि नए बायलॉज़ से बनी 10 हज़ार बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है, जो एक नई शुरूआत है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और पैक्स की वायबिलिटी के लिए मॉडल बायलॉज़ बनाए गए जिन्हें सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मॉडल बायलॉज़ के तहत अब पैक्स कई प्रकार की अलग-अलग नई गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार ने 2500 करोड़ रूपए खर्च कर हर पैक्स को कंप्यूटर और सॉप्टवेयर दिए हैं और कई प्रकार की नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसे सफल बनाने के लिए हमें तकनीक को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि पैक्स में प्रोफेशनलिज़्म लाकर इसके माध्यम से पूरे सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत करना होगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंक हो या पैक्स, हमें विश्वास के साथ नई तकनीक को जानने वाले युवाओं को साथ लाना होगा, तभी हम सहकारिता को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, श्री देवेन्द्र फडणवीस, श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजित पवार की डबल इंजिन की सरकार महाराष्ट्र को सच्चे अर्थों में सहकारिता की काशी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता ही हर गांव में रोजगार का ज़रिया हो सकता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत बड़ी मदद की है और इथेनॉल ने चीनी मिलों के मुनाफे को बढ़ाया है। चीनी के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 10 लाख टन चीनी के निर्यात का फैसला लिया जिसका सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए एक रैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। श्री शाह ने कहा कि 7 प्रमुख क्षेत्रों- पैक्स, डेयरी, मत्स्यपालन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आवास क्रेडिट सोसायटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव और खादी ग्रामोद्योग - में हम रैंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके तहत ऑडिट, गतिविधियां, सेवाएं, वित्तीय प्रदर्शन, आधारभूत संरचना और ब्रांडिंग जैसे कई मानाक तय किए हैं, जिनको मिलाकर 100 अंक रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे विश्वसनीय बनाया जाएगा जिससे इसके आधार पर किसी भी बैंक को पैक्स को पैसा देने में दिक्कत न हो।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि और समद्धि से आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के कैलेंडर का उद्घाटन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंब्रेला संगठन के कार्यालय की शुरूआत और 10 हज़ार नए पैक्स के लिए पहला प्रशिक्षण शुरू हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में गुजरात के महान सहकारिता नेता श्री त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर त्रिभुवन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा करेगी, जो सभी क्षेत्रों के लिए हमें प्रोफेशनल उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र आने वाले दिनों में कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और युवाओं के लिए रोज़गार और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उद्यानिकी फसलों के लिए बनेगी पृथक मंडी : मंत्री श्री कुशवाह

उद्यानिकी मंत्री ने एक माह में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

भोपाल :प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय पर अमल के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में उद्यानिकी बोर्ड की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में हुई।

मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलावाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रमुख 11 कृषि उपज मंडी इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर, जिनमें एक लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है, ऐसी मंडियों में प्रथम चरण में बोर्ड बनावर उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिये पृथक से परिसर बनेगा। मंत्री श्री कुशवाह ने निर्देश दिये कि संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक एमपी एग्रो एवं विशेषज्ञों की टीम एक माह में विस्तृत सर्वे कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। श्री कुशवाह ने कहा यह उद्यानिकी उपज मंडी पूर्णत: हाईटैक होंगी, जिनमें फसल उत्पादक किसान सीधा उपभोक्ताओं को अपनी फसल का विक्रय कर सकेगा। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।

वर्तमान में म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में किया जाता है। प्रदेश की 25, कृषि उपज मंडी समिति है इनमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियाँ अधिसूचित है। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने पर फल-फूल सब्जी फसल के लिये पृथक नवीन परिसर बनाये जाएगें। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकिंग, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएँ विकसित की जायेंगी।

उद्यानिकी योजनाओं के लिये नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाये

मंत्री श्री नारायन सिंह कुशवाह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये है कि उद्यानिकी विभाग को हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए नवीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाये। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाये, जिससे अधिक से अधिक किसान लाभावित हो सकेंगे।

संचालक उद्यानिकी श्रीमती प्रिति मैथिल ने कहा कि हितग्राहियों से उद्यानिकी विभाग के पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्रतानुसार हितग्राहियों का चयन उनकी आवश्यकतानुसार किया जाएगा। उन्होंने यह प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है।

बैठक में प्रबंध संचालक म.प्र. कृषि उपज मंडी बोर्ड, श्री कुमार पुरूषोत्तम, प्रबंध संचालक एम.पी.एग्रो श्री दिलीप कुमार और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अपेक्स बैंक - भोपाल में 76 वें गणतंत्र दिवस पर श्री बर्णवाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

भोपाल। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, सहकारिता एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक श्री अशोक बर्णवाल द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बैंक के प्रांगण में फहराया एवं सभी ने राष्ट्रीय गान गाया। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने गान के पश्चात "भारत माता की जय" एवं "हिन्दुस्तान-अमर रहे" के सामूहिक नारे भी लगवाये। इस अवसर पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें,, मध्यप्रदेश श्री मनोज पुष्प, उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा, वि.क.अ. श्री अरूण मिश्र श्रीमति कृति सक्सेना, उप महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल, श्री के.टी. सज्जन, श्री अरविन्द बौद्ध वि.क.अ., प्रबंधक श्री विवेक मलिक, श्री समीर सक्सेना, श्री अजय देवड़ा, श्री आशीष राजोरिया सहित बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित हुए।

सहकारी संस्थाओं में झण्डा फहराने की झलकियां

जिला सहकारी संघ मर्यादित, रतलाम में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर तिरंगा झण्डा फहराया गया

श्री गुजराती रामी माली समाज नवयुवक साख सहकारी संस्था मर्यादित, नौगांव, जिला धार में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर तिरंगा झण्डा फहराया गया

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

नौगांव, जिला छतरपुर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव में एनसीसीई, नई दिल्ली के सहयोग से टीकमगढ़ जिले की मत्स्य सहकारी समितियों के पदाधिकारियों व सदस्यों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम दिनांक 28 से 30 जनवरी 2025, का उद्घाटन श्री अनूप तिवारी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नौगांव द्वारा मां सरस्वती की फोटो को माल्यार्पण करके किया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का आव्हान किया। श्री एस के साहू, मत्स्य निरीक्षक, छतरपुर द्वारा मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। श्री सूरजभान पटेल, एसएसडीओ, कृषि विभाग, नौगांव द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र के प्राचार्य द्वारा अतिथियों का स्वागत व कार्यक्रम का संचालन किया गया।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका

जबलपुर में दो दिवसीय महिला सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

जबलपुर। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी आंदोलन एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। सहकारिता का उद्देश्य है समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें संगठित कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहकारी प्रशिक्षण केंद्र,जबलपुर में 22 और 23 जनवरी 2025 को कौशल उन्नयन और नेतृत्व विकास पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से उद्यमशीलता और नेतृत्व विकास के लिए प्रेरित करना था। महिलाओं को सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की जानकारी देकर उन्हें बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के गठन और संचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया।

प्रमुख वक्ताओं का योगदान

समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने सहकारी आंदोलन को "जन आंदोलन" बताते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सहकारिता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सहकारी समिति गठन प्रक्रिया पर चर्चा की।

विशेष अतिथि डॉ. प्रशांत कौरव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ने म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता न केवल आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह सामुदायिक विकास को भी सशक्त करता है।

पूर्व प्राचार्य श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने महिलाओं को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रेरित किया और वित्तीय लेखांकन तथा आवश्यक रिकॉर्ड प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य श्री वी. के. बर्वे ने महिला सहकारी समितियों में व्यवसाय नियोजन, विक्रय कला, कार्यकारिणी समिति गठन और व्यवसाय की नई संभावनाओं पर चर्चा की। कौशल उन्नयन सत्र: मास्टर ट्रेनर श्रीमती मोनिका मुदगल ने महिलाओं के कौशल उन्नयन पर जानकारी दी। नेतृत्व विकास सत्र: श्रीमती किरण भारद्वाज ने नेतृत्व विकास के महत्व और इसके व्यवहारिक पक्ष पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। सहकारी प्रबंधन: प्रशिक्षक श्री पीयूष राय, श्री जयकुमार दुबे, और श्री अखलेश उपाध्याय ने सहकारी समितियों के उद्देश्यों, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों, और आमसभा की बैठकों के संचालन की विधि पर विस्तृत चर्चा की।

सहकारिता और महिलाओं का योगदान

सहकारिता एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को सामूहिक रूप से काम करने, आर्थिक निर्णय लेने और उद्यमशीलता का कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है। आज महिलाएं कृषि, विपणन, क्रेडिट, और बहुउद्देश्यीय समितियों के माध्यम से सहकारिता की मुख्यधारा में आ रही हैं। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास के लिए सहकारिता का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन प्रशिक्षक श्री पीयूष राय द्वारा किया गया। जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश बाजपेई का सहयोग सराहनीय रहा। समापन पर लेखापाल श्री एन. पी. दुबे ने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

सहकारिता में कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास

नौगांव में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

नौगांव: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव भवन में 17 और 18 जनवरी 2025 को बुंदेलखंड दुग्ध सहकारी समितियों के संचालकों और सदस्यों के लिए दो दिवसीय "कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ 17 जनवरी को श्री कल्याण शिवहरे, पर्यवेक्षक द्वारा किया गया, जिन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों की योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद श्री सूरजभान पटेल, एसएडीओ कृषि विभाग, नौगांव ने कृषि और पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर श्री महेश साहू, हार्डवेयर इंजीनियर ने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव तथा तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्रदान की। प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित ने सहकारिता में कौशल उन्नयन और नेतृत्व विकास के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही साइबर अपराध से बचाव के उपायों पर भी विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम के दूसरे दिन श्री प्रकाश गरेहते, निदेशक, SBI R-SETI ने उद्यमिता विकास और सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ ही जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री हृदेश रॉय ने सहकारिता में नवाचार पर प्रेरणादायक वक्तव्य दिया और नए तकनीकी प्रयोगों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 36 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित कर किया गया, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी समितियों के संचालन में कौशल और नेतृत्व विकास को प्रोत्साहन देने में सफल रहा, और प्रतिभागियों तथा क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा सराहा गया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

देश को सशक्त और समृद्ध बनाने....

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय ग्रामों में योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" प्रारम्भ किया है। अभियान में 11 हजार से अधिक ग्रामों में निवासरत 18 लाख 58 हजार जनजातीय परिवारों की 93 लाख 23 हजार आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को 728 करोड़ रुपए की प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। प्रदेश के 89 विकासखंडों में 100-100 सीटर आवासीय छात्रावास बनेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातीय की बहनों को वर्ष 2024 में 325 करोड़ रुपए से अधिक की आहार अनुदान सहायता दी गई है। प्रदेश में पीएम जन-मन योजना में तेज गति से विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों के 11 लाख से अधिक भाई-बहनों को लाभान्वित करने 7 हजार 300 करोड़ रुपए के अधोसंरचना कार्य हो रहे हैं। देश में सर्वप्रथम शिवपुरी में 500 पीएम जन-मन आवास एवं बालाघाट में पहली सड़क का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई स्मृति एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्मृति जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाए गए हैं। शौर्य संकल्प योजना में बटालियन बनाकर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ हो गए हैं। प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उन्नत सुविधाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। प्रदेश में 3 नये विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद नाम भी बदलकर कुलगुरु किया है। आगर-मालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय ज्ञान परम्परा हेतु रामायण व गीता वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयुष चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन शुरू हो गया है। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, बालाघाट और मुरैना में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। नए 530 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास का नया इतिहास बन रहा है। वर्तमान 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को, वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश को दो अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना की सौगात दी है। देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना में उत्तरप्रदेश के साथ प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 10 जिलों को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, प्रदेश के 11 जिलों में विकास का नया अध्याय लिखेगी। सिंगरौली जिले में 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई की चितरंगी और दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई की जावद-नीमच और बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में सफलता की अनेक कहानियां लिखकर मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 96 हजार से अधिक दीदियाँ लखपति बनी है और 62 लाख ग्रामीण बहनें आत्म-निर्भर हुई हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक राज्य में लागू कर मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, प्रदेश को दूसरा स्वच्छतम् राज्य और भोपाल को स्वच्छतम् राजधानी के पुरस्कार मिले हैं। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड का सम्मान एवं "बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म" श्रेणी में प्रतिष्ठित "ग्लोबल टूरिज्म अवॉर्ड" मिला है। मध्यप्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट के साथ-साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। भोपाल का रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनेगा।

गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह में सांसद श्री वी.डी. शर्मा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने ली परेड की सलामी

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद परेड कमांडर श्री करणदीप सिंह के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया गया। टूआईसी श्री अतुल कुमार सोनी के नेतृत्व में परेड में विभिन्न बलों की 20 टुकड़ियां शामिल थीं। इन 20 दलों ने देशभक्ति की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट किया। परेड के बाद आकाश में तिरंगे के रूप में गुब्बारे छोड़े गये।

जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां

राज्य स्तरीय समारोह में जनजातीय संस्कृति पर केन्द्रित गोण्ड ठाच्या की प्रस्तुति हुई। यह नृत्य जनजातीय समुदाय में दीपावली के बाद किया जाता है। लोक कलाकारों ने बांसुरी की मधुर धुन और हाथ, पैर एवं कमर का सुंदर संयोजन कर विविध मुद्राओं से नृत्य को आकर्षक बनाया। कार्यक्रम में कोरकू जनजाति के गदली-थापटी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। लोक कलाकरों ने ठोलक की लय-ताल पर हाथों और पैरों की विभिन्न मुद्राएं बनाते हुए गोल घेरे में कोरकू नृत्य प्रस्तुत किया।

आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन

गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों के माध्यम से प्रदेश की प्रगति, सुशासन जनभागीदारी से समग्र विकास को प्रदर्शित किया गया। 20 शासकीय विभागों की झांकियों को प्रदर्शन किया गया। उद्यानिकी विभाग की झांकी में उद्यानिकी फसलों से किसानों की बढ़ती आय को दर्शाया गया। प्रदेश में उद्यानिकी मंडियों का संचालन और वर्तमान में 15 उद्यानिकी फसलों का जीआई पंजीयन को प्रदर्शित किया गया। आयुष विभाग की झांकी में आयुष हेल्थ-वेलनेस सेंटर, समुद्र मंथन से आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति और प्रदेश में अत्याधुनिक आयुर्वेद अस्पतालों के संचालन को प्रदर्शित किया गया। उद्योग विभाग की झांकी में बुधनी के लकड़ी के खिलौने, इन्वेस्टर्स मीट और बुरहानपुर के पावर लूम को दिखाया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की झांकी में दलहन-तिलहन के बढ़ते उत्पादन, रानी दुर्गावती श्रीअन्न योजना से कोदों, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा के बढ़ते उत्पादन को दिखाया गया। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की झांकी में खादी कपड़े की बुनाई और वस्त्र निर्माण करने की कला, रेशमी वस्त्र कला और माटीकला के पारंपरिक साधनों को विकसित करते हुए इलेक्ट्रिक चरखों से रंगीन कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को दिखाया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग की झांकी में प्रदेश के 11 खेल अकादमियों के संचालन, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश की झाँकी में पेरिस ओलंपिक, पैरालम्पिक में 6 खिलाड़ियों द्वारा 3 काँस्य पदक अर्जित करने की उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया। गृह विभाग की झांकी में पुलिस बैंड की प्रभावी प्रस्तुति को दिखाया गया। प्रदेश में व्यापक रूप में पुलिस बैंड यूनिट का विस्तार किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस द्वारा जनजातीय समुदाय के लिये चलाये जा रहे "जनमैत्री" अभियान को दर्शाया गया।

किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूँ पर मिलेगा 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस

भोपाल : राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिये निरंतर कार्य कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये प्रदेश के पंजीयन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन के लिये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। गेहूँ उपार्जन के लिये समर्थन मूल्य 2425 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150 रूपये प्रति क्विंटल अधिक है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मध्यप्रदेश बना "बैस्ट परफॉर्मिंग स्टेट"

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने दी बधाई

भोपाल :केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए "बैस्ट परफॉर्मिंग स्टेट" का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी और आशा व्यक्ति की है कि भविष्य में भी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल रहेगा।

केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित एक दिवसीय उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार मध्यप्रदेश के दल को प्रदान किया। प्रदेश से योजना के नोडल अधिकारी डॉ. भगवान मधनानी, डॉ. शिवदत्त श्रीवास्तव और डॉ. प्रखर भार्गव, उप संचालक ने पुरस्कार प्राप्त किया। केन्द्रीय सचिव, पशुपालन एवं डेयरी श्रीमती अल्का उपाध्याय, पशुपालन आयुक्त डॉ अभीजीत मिश्रा तथा डॉ. पी.एस. पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी द्वारा भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के अधिकारियों को बधाई दी गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश में अभी तक 4800 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 530 प्रकरणों में राशि 387.23 करोड़ रूपये बैंकों से स्वीकृत होकर केन्द्र सरकार द्वारा 450 प्रकरणों में 155.36 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत प्रकरणों में लगभग 250 उद्यमियों को प्रथम किश्त और 32 को द्वितीय किश्त की अनुदान राशि स्वीकृत होकर प्राप्त हो चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

उत्कृष्ट उद्यमी भी हुए सम्मानित

कॉनक्लेव में पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और केन्द्रीय उद्यमिता विकास योजनाओं राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम और पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत लाभांवित उद्यमियों में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाईयों को भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यकम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के जीत सिंह सिसोदिया (भोपाल) तथा नवनीत जैन (हरदा) को चारा उत्पादन हेतु, श्रीमती शोभा दांगी (राजगढ़) तथा निमिश चावड़ा (शाजापुर) को बकरी पालन तथा श्री यशपाल खन्ना (कटनी) को मुर्गी पालन अंतर्गत उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया। इसी तरह पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत धार जिले की बदनावर तहसील में स्थापित एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. को पशु आहार केटेगरी में सराहनीय कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में स्थापित बेकरविले स्पेशलिटिस प्रा.लि. को दुग्ध प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन केटेगरी में उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया गया। इन दोनों इकाईयों की ऑनलाइन लॉन्चिंग भी केंद्रीय पशुपालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा कार्यकम स्थल से की गई।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में 'सहकारिता सम्मेलन' को संबोधित किया और सहकारिता से संबंधित विभिन्न कार्यों का शुभारंभ किया

मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को सहकारिता मंत्रालय साकार कर रहा है, जिससे सहकारिता से जुड़े बहनों-भाइयों को प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं

'सहकारिता' आत्मनिर्भरता की सबसे सुंदर व्याख्या है और सहकारिता ही किसानों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने का सशक्त माध्यम है

नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड किसानों की आर्गेनिक उपज को बेचकर उससे प्राप्त मुनाफे को सीधा किसानों के खाते में पहुंचा रही है

तीन नई मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव किसानों की आय में वृद्धि और वैश्विक बाजार तक उनकी पहुँच सुनिश्चित कर रही हैं

महाराष्ट्र में सहकारी चीनों मिलों में 15 हजार करोड़ रुपए का आयकर विवाद था, जिसे मोदी सरकार ने समाप्त कराया

मोदी सरकार ने चीनी मिलों का इनकम टैक्स कम किया और इथेनॉल ब्लेंडिंग योजना लाई, जिससे उद्योगों और किसानों को आर्थिक मजबूती मिली

वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने सहकारी ब्रांड के तहत काजू की खेती करने वाले हजारों किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसर किया

नासिक में बनाई गई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थानीय किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 'सहकारिता सम्मेलन' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यों का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन में केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने किसान, खेतिहर मजदूर और इसके साथ-साथ सेना को भी मजबूत करना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान जय किसान और मृदा परीक्षण की लेबोरेट्री बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम किया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पहले चर्चा होती थी कि खेती में कोई मुनाफ़ा नहीं है, लेकिन उनका आज भी दृढ़ विश्वास है कि यदि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई शंका नहीं कि आज भी खेती मुनाफे वाला बिजनेस है। उन्होंने कहा कि पहले किसान परम्परागत तरीके से खेती करते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि उनके खेत की मिट्टी में किस चीज़ की मात्रा अधिक या किसकी मात्रा कम है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जब मिट्टी के परीक्षण की बात की, तब पता चला कि किसान ऐसे खाद खेत में डालते थे, जिनकी ज़रुरत ही नहीं थी और न्यूट्रिशन के लिए जिस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए था, वह नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नासिक जिले में बनाई गई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थानीय किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ेगा कि किसान जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे, उसमें पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं, डीएपी कितना डालना है और कौन सी फसल की खेती करने से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने एक साथ कई पहल की है। उन्होंने कहा कि आज वर्चुअल माध्यम से बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, जहां प्रतिदिन 24 टन काजू प्रोसेस किया जाएगा और इससे 18,000 किसानों को काजू की खेती के लिए उचित दाम मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि 1500 से ज्यादा गिर की गायें भी लाई गई हैं, जिससे सभी प्रकार के उत्पाद भी बनेंगे और गाय के गोबर एवं गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की भी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इन पहलों से किसान समृद्ध बनेंगे और इससे धरती माता की भी रक्षा होगी।

श्री अमित शाह ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम भी नहीं मिलते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता मंत्रालय ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) नाम की संस्था बनाई है। यह मल्टीनेशनल संस्था है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज उनसे खरीद कर बाज़ार में बेचती है और उससे प्राप्त मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाती है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग कई सालों सेमांग कर रहे थे कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, लेकिन उनकी मांग पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो देश भर के किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कुछ है तो वह सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध नहीं बन सकता, इसलिए मोदी जी ने 'सहकार से समृद्धि' का नारा दिया है जिसे चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अब काजू के अलावा अनार अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, सेब, केसर और आम की खेती सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने सौर ऊर्जा, बायो फ्यूल, सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य, अगरबत्ती, ऑर्गेनिक खेती और सरकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का सराहनीय काम किया है, साथ ही उन्होंने देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जवान और किसान सिर्फ दो वर्ग ऐसे हैं जो बारिश, धूप, ठंड की चिंता किए बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज सहकारिता के इस कार्यक्रम के माध्यम से जवान और किसान दोनों ही साथ आए।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के प्रोडक्ट के निर्यात, प्रमाणिक मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उपज देने वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग, और ब्रांडिंग के लिए तीन नई मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। उन्होंने कहा कि अमूल, कृभको और इफको के पैटर्न पर तीनों कोऑपरेटिव संस्थाएं अगले 10 साल में इस देश के किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश मे गोदाम बनाये जा रहे हैं और PACS को भी बहुआयामी बनाने का काम किया गया है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में सहकारी चीनों मिलों में 15 हजार करोड़ रुपए के आयकर का विवाद था, जिसे मोदी सरकार ने समाप्त कराया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 46 हजार करोड़ रुपए के नए टैक्स को कम करने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से देश की कई कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से भी कमाऊ यूनिट बनाने का काम हुआ है। श्री शाह ने विपक्षी नेताओं से सवाल किया कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र, PACS, चीनी मिलों और किसानों के लिए क्या किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग की योजना लेकर आए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, PACS का कम्प्यूटराइजेशन किया, PACS के मॉडल बायलॉज़ बनाए और PACS को मल्टीडाइमेन्शनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम किया।

सहकारिता और गणतंत्र के संगम का उत्सव: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस

भोपाल। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के मुख्यालय और सभी सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों पर राष्ट्रप्रेम, सहकारिता और उत्साह के साथ यह ऐतिहासिक दिवस मनाया गया। संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने मुख्यालय में राष्ट्रध्वज फहराया और सामूहिक राष्ट्रगान से समारोह का शुभारंभ हुआ।

गौरवमयी उपस्थिति:

समारोह में संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, उप प्रबंधक श्री गणेश प्रसाद मांझी, लेखाधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल, राज्य समन्वयक श्री संतोष येड़े, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षक उपस्थित रहे। सीड संस्था के अध्यक्ष, सचिव और उनका समस्त स्टाफ भी इस अवसर पर उपस्थित रहा।

प्रबंध संचालक का प्रेरणादायक संदेश:

अपने उद्बोधन में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने सहकारिता और गणतंत्र के बीच अटूट संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमारे संविधान के चार स्तंभ - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, सहकारिता के मूल्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए सहकारी समितियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना होगा।उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा, "सहकारिता केवल वित्तीय लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मंच है। सामूहिक प्रयासों से हम न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि समाज में स्थिरता और समृद्धि भी ला सकते हैं।"

प्राचार्यों ने बढ़ाया उत्साह:

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के प्राचार्य ने कहा, "शिक्षा और अनुशासन हमारे संस्थान की पहचान है। हम सबको मिलकर सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।"

इसी क्रम में, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के प्राचार्य ने प्रेरणादायक विचार व्यक्त करते हुए कहा, "सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। सहकारिता सामूहिक विकास का प्रतीक है, और हमें इसे मजबूत बनाना है।"

नौगांव केंद्र के प्राचार्य श्री पुरोहित ने कहा, "सहकारिता का मंत्र - 'सबका साथ, सबका विकास' ही हमारे गणराज्य के आदर्शों का प्रतीक है। सहकारी आंदोलन किसानों और श्रमिकों को आर्थिक स्वतंत्रता देने का सशक्त माध्यम है।"

संकल्प और सामूहिक प्रयास का प्रतीक:

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहकारी आंदोलन को डिजिटल युग के अनुकूल और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। यह समारोह सहकारिता के सामूहिक प्रयास और गणतंत्र के आदर्शों का जीवंत उदाहरण बना।

सहकार से समृद्धि का मंत्र:

76वें गणतंत्र दिवस के आयोजन ने सहकारिता के महत्व और उसके सामूहिक प्रयासों को समाज में समृद्धि और स्थिरता लाने के प्रेरणास्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। गणतंत्र और सहकारिता के इस संगम ने "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य को एक नई दिशा दी।

गणतंत्र दिवस पर भोपाल में सहकारिता विभाग की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

'विरासत से विकास की ओर' ने दर्शकों का दिल जीता

भोपाल। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य परेड में सहकारिता विभाग की झांकी'विरासत से विकास की ओर'विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस झांकी ने सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया।

झांकी की मुख्य विशेषताएं:

- देश की पहली सहकारी समिति पिपरिया (1905) और सहकारी बैंक सिहोरा (1907) का ऐतिहासिक प्रदर्शन।
- M-PACS (बहुउद्देश्यीय पैक्स), अपेक्स बैंक और कृषक साख संस्थाओं की आधुनिक भूमिका।
- 0% ब्याज पर 45 लाख किसानों को रु. 20,000 करोड़ का कृषि ऋण।
- 4,600 केंद्रों के माध्यम से 42 लाख टन धान का उपार्जन।
- 100% पैक्स कम्प्यूटरीकरण और जन औषधि केंद्रों की स्थापना।
- दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड और सहकारी समितियों के नवाचार।

नवाचार और नई पहलें: सहकारी समितियों ने पेट्रोल पंप, रसोई गैस विक्रय, सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प, और पर्यटन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं। 322 डेयरी समितियों के गठन और तेंदूपत्ता श्रमिकों को रु. 600 करोड़ का वार्षिक पारिश्रमिक इस प्रयास के बड़े उदाहरण हैं।

निर्माण में नेतृत्व: झांकी का निर्माण सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल और आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में किया गया। इसकी परिकल्पना और सफल कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन और महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदेश: झांकी ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के संदेश'सहकारी समितियों के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण'को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। यह झांकी सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाने के साथ प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का प्रतीक बनी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।